



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 99]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 30, 2004/वैशाख 10, 1926

No. 99]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 30, 2004/VAISAKHA 10, 1926

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

( अनुसूचित जाति विकास प्रभाग )

आदेश

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2004

सं. 12016/9/2003-एससीडी ( आर.एल. सैल )-भाग IX.— भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (अनुसूचित जाति विकास प्रभाग) ने भारत के राजपत्र, भाग I, खण्ड 1, तारीख 22 नवम्बर, 2003 में प्रकाशित संकल्प सं. 12016/9/2003-एससीडी (आर.एल. सैल) द्वारा अनधिसूचित जनजातियों, खानाबदोश और अर्ध खानाबदोश जनजातियों के विकासात्मक पहलुओं का अध्ययन करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का एक वर्ष के लिए गठन किया था।

2. और केन्द्रीय सरकार, उक्त आयोग में अध्यक्ष, सदस्यों और सदस्य-सचिव की अर्हता, नियुक्ति की पद्धति, उसके पद में किसी रिक्ति को भरने की बाबत उपर्युक्त संकल्प के अतिरिक्त कतिपय मार्गदर्शक सिद्धान्त विनिर्दिष्ट करना आवश्यक समझती है।

### 3. अर्हताएं

- (i) अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य-सचिव योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाले व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे।
- (ii) अध्यक्ष, या तो खानाबदोश, अर्ध खानाबदोश, अनधिसूचित जनजातियों अनुसूचित जाति के या अनुसूचित जनजातियों के ऐसे विशिष्ट वृत्तिकों में से नियुक्त किया जाएगा जो अपने व्यक्तित्व और स्वार्थहीन सेवाओं के अभिलेख द्वारा लक्षित समूहों में विश्वास पैदा करते हैं।

- (iii) सदस्यों में से कम से कम एक सदस्य खानाबदोश, अर्ध खानाबदोश, अनधिसूचित जनजातियों, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से नियुक्त किया जाएगा ;
- (iv) अध्यक्ष, सदस्यों और सदस्य-सचिव की न्यूनतम अर्हता किसी विद्या शाखा में स्नातक डिग्री होगी ;
- (v) अध्यक्ष के लिए न्यूनतम आयु 50 वर्ष होगी ;
- (vi) अध्यक्ष और सदस्यों का कोई आपराधिक अभिलेख नहीं होगा ;
- (vii) चार सदस्यों में से एक सदस्य को सदस्य-सचिव के रूप में नियुक्त किया जाएगा ।

4. पदावधि - अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार पद धारण करेगा ।

5. वेतन और भत्ते -

- (क) प्रास्थिति, वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं, जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष, सदस्यों और सदस्य-सचिव की वास सुविधा भी है, वह होगी जो भारत सरकार द्वारा अवधारित की जाएगी किन्तु भारत सरकार के सचिव से कम नहीं होगी ।
- (ख) जहां कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश है या कोई सेवानिवृत्त सरकारी सेवक है या किसी अन्य संस्था या स्वशासी निकाय का सेवानिवृत्त सेवक है और किसी पूर्ववर्ती सेवा की बाबत पेंशन प्राप्त कर है, अध्यक्ष, सदस्य या सदस्य-सचिव नियुक्त किया जाता है, वहां इन नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय वेतन भारत सरकार के किसी सचिव को अनुज्ञेय वेतन और भत्तों के समान होगा, और उसमें से उस पेंशन की रकम और यदि उसने पेंशन के किसी भाग के बदले में उसका संराशिकृत मूल्य प्राप्त किया है तो पेंशन के उस भाग की रकम कम कर दी जाएगी ।
- (ग) जहां अध्यक्ष, कोई सदस्य या सदस्य-सचिव, संसद् या किसी राज्य विधान मंडल का सदस्य है, वहां वह, यथास्थिति, संसद् ( निरर्हता निवारण ) अधिनियम, 1959 ( 1959 का 10 ) की धारा 2 के खण्ड (क) में परिभाषित, भत्तों से भिन्न, या ऐसे

भत्तों से भिन्न, यदि कोई हों, किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा जो राज्य के विधान मंडल का कोई सदस्य राज्य विधान मंडल की सदस्यता के लिए निरर्हता के निवारण से संबंधित राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऐसी निरर्हता उपगत किए बिना प्राप्त कर सकेगा ।

- (घ) यदि, जहां, ऊपर का खण्ड 5(ख) और 5(ग) लागू नहीं होता है तो भारत सरकार के सचिव को अनुज्ञेय वेतन और भत्ते आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य-सचिव को लागू होंगे ।

6. छुट्टी -

अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य-सचिव निम्नलिखित छुट्टियों के हकदार होंगे :-

- (क) समय-समय पर यथा सशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अनुसार उपार्जित छुट्टी, अर्ध वेतन छुट्टी और परिवर्तित छुट्टी ; और  
(ख) असाधारण छुट्टी अनुज्ञेय नहीं होगी ।

7. चिकित्सा सुविधाएं -

अध्यक्ष, सदस्यों और सदस्य-सचिव को वे चिकित्सा सुविधाएं होंगी जो भारत सरकार के किसी सचिव को अनुज्ञेय हैं ।

8. किसी स्थायी या अस्थायी रिक्ति की दशा में व्यवस्था -

यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है या यदि अध्यक्ष किसी कारण से अनुपस्थित है या अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तो उन कर्तव्यों का निर्वहन ज्येष्ठतम सदस्य द्वारा तब तक किया जाएगा जब तक, यथास्थिति, नया अध्यक्ष अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है या विद्यमान अध्यक्ष अपने पद को फिर से नहीं संभाल लेता है ।

9. पदत्याग और हटाया जाना -

- (1) अध्यक्ष, कोई सदस्य और सदस्य-सचिव, राष्ट्रपति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेगा ।

(2) राष्ट्रपति, अध्यक्ष, किसी सदस्य या सदस्य-सचिव को आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा, यदि वह -

- (i) कोई दिवालिया न्यायनिर्णीत हो जाता है ; या
- (ii) अपने पद धारण के दौरान अपने पद के कर्तव्यों से बाहर किसी संदत्त नियोजन में लगता है ; या
- (iii) राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने में अनुपयुक्त रहता है ; या
- (iv) किसी अपराध के लिए जिसमें राष्ट्रपति की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है दोषसिद्ध और कारावास से दण्डादिष्ट किया जाता है ; या
- (v) कार्य करने से इंकार करता है ; या
- (vi) आयोग से अनुपस्थिति की इजाजत लिए बिना, आयोग की लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित रहता है ; या
- (vii) राष्ट्रपति की राय में अध्यक्ष या किसी सदस्य की हैसियत का इस प्रकार दुरुपयोग किया है जिससे उस व्यक्ति के उस पद पर बने रहना आयोग के हितों के लिए हानिकारक होगा :

परन्तु अध्यक्ष, किसी सदस्य या सदस्य-सचिव को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया है ।

पी. नारायण मूर्ति, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT  
(Scheduled Castes Development Division)**

**ORDER**

New Delhi, the 29th April, 2004

**No. 12016/9/2003-SCD (R.L. Cell)-Part-IX.**—Whereas the Government of India in the Ministry of Social Justice and Empowerment (Scheduled Castes Development Division) has constituted a National Commission for one year to study the developmental aspects of the Denotified Tribes, Nomadic and Semi-nomadic Tribes, vide the Resolution No. 12016/9/2003-SCD (R.L. Cell), published in the Gazette of India, Part I, Section 1, dated the 22nd November, 2003.

2. And whereas the Central Government considers it necessary to specify certain guidelines in addition to the aforesaid Resolution with regard to the qualification, method of appointment of the Chairperson, Members and Member-Secretary, filling up of any vacancy in office thereof, resignation and removal, the terms of office and salary and allowances etc. in the said Commission.

**3. Qualifications**

(i) The Chairperson, Members and Member-Secretary shall be appointed from amongst persons of ability, integrity and standing.

(ii) The Chairperson shall be appointed from amongst eminent professionals belonging to either of the Nomadic, Semi-Nomadic, Denotified 'Tribes', Scheduled Caste or Scheduled Tribes, who inspires confidence amongst the target groups by his/her personality and record of selfless service;

(iii) At least one of the Members shall be appointed from amongst persons belonging to the Nomadic, Semi-Nomadic, Denotified 'Tribes', Scheduled Caste or Scheduled Tribes.

(iv) The minimum qualification for Chairperson and Members and Member-Secretary shall be a Graduate degree in any discipline.

(v) The minimum age for the Chairperson will be 50 years.

(vi) The Chairperson and Members will not have a criminal record.

(vii) Out of four Members, one Member shall be appointed as Member- Secretary.

4. Term of Office -The Chairperson and every Member shall hold office for a term in accordance with the notification published in the Gazette of India.

5. Salaries and allowances

(a) The status, salaries, allowances, and other facilities including accommodation of the Chairperson, Members and Member-Secretary shall be as determined by the Government of India but shall not be less than Secretary to the Government of India.

(b) Where any person, being a retired judge of the Supreme Court or of a High Court or a retired government servant or retired servant of any other institution or autonomous body and in receipt of a pension in respect of any previous service, is appointed as the Chairperson, a Member or Member-Secretary, the salary admissible to him under these rules shall be the salary and allowances admissible to a Secretary to the Government of India, reduced by the amount of that pension and if he/she had received in lieu of a portion of the pension, the commuted value thereof, by the amount of that portion of the pension.

(c) When the Chairperson, any Member or Member-Secretary is a Member of Parliament, or a State Legislature he/she shall not be entitled to any remuneration other than the allowances, defined in clause (a) of section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 (10 of 1959) or as the case may be, other than the allowances, if any, which a Member of the Legislature of the State may, under any law for the time being in force in the State relating to the prevention of

disqualification for membership of the State Legislature receive without incurring such disqualification.

(d) In case where the clauses 5(b) and 5(c) above are not applicable, then the Salary and allowances as are admissible to the Secretary to the Government of India shall be applicable to the Chairperson, Members and Member-Secretary of the Commission.

#### 6. Leave

The Chairperson, Members and Member-Secretary shall be entitled to leave as follows:-

(a) earned leave, half pay leave and commuted leave in accordance with the Central Civil Services(Leave)Rules,1972 as amended from time to time, and

(b) extraordinary leave shall not be as admissible.

#### 7. Medical Facilities

The Medical Facilities to the Chairperson, Members and Member-Secretary shall be as admissible to a Secretary to the Government of India.

#### 8. Arrangement in case of a permanent or temporary vacancy

If the office of the Chairperson becomes vacant or if the Chairperson is for any reason absent or unable to discharge the duties of his/her office, those duties shall until the new Chairperson assumes office or the existing Chairperson resumes his/her office as the case may be, be discharged by the senior most Member.

#### 9. Resignation and Removal

(1) The Chairperson, a Member and Member-Secretary, may, by notice in writing under his/her hand addressed to the President, resign his/her post.

(2) The President may by order remove from office the Chairperson, a Member or Member-Secretary if he/she,

(i) is adjudged as an insolvent; or

(ii) is engaged during his term of office in any paid employment outside the duties of his office; or

- (iii) is, in the opinion of the President, unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body; or
- (iv) is convicted and sentenced to imprisonment for an offence, which in the opinion of the President, involves moral turpitude; or
- (v) refuses to act; or
- (vi) is without obtaining leave of absence from the Commission, absents from three consecutive meetings of the Commission; or
- (vii) in the opinion of the President, has so abused the position of the Chairperson, or a Member as to render that person's continuance in office detrimental to the interests of the Commission:

Provided that the Chairperson, a Member or Member-Secretary shall not be removed until he/she has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter.

P. NARAYANA MURTHY, Jt. Secy.